राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,झारखंड के 61वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत्त

Minutes of the 61st Quarterly Meeting of SLBC, JHARKHAND

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 61वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन दिनांक 10.11.2017 को होटल रेडिसन ब्लू ,रांची में किया गया। बैठक का आरम्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,झारखंड के महाप्रबंधक श्री प्रसाद जोशी द्वारा सभा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों के स्वागत संबोधन से हुआ। श्री प्रसाद जोशी ने बैंको द्वारा चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्यों के बावजूद वर्तमान तिमाही में पिछली तिमाही से अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर कार्य किए जाने पर संतोष व्यक्त किया । उन्होने खासकर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य मे आयोजित किए गए 'गरीब कल्याण मेला' एवं 'मुद्रा प्रोत्साहन अभियान' के दौरान पिछड़े वर्गों एवं सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण कार्यक्रमों में बैंको द्वारा संतोषप्रद ऋण संवितरण की सराहना की और साथ ही सभी हितधारकों को लक्ष्यों को यथाशीघ्र प्राप्त करने की सलाह दी । उन्होने SLBC की बैठक के दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण में ठोस और कारगर चर्चा किए जाने की आशा की जिससे राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ किया जा सके ।

तत्पश्चात मंच पर आसीन झारखंड राज्य के अपर मुख्य सचिव-सह-विकास आयुक्त श्री अमित खरे;संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री मदनेश कुमार मिश्रा ;प्रधान सचिव,समाज कल्याण,झारखंड सरकार, श्री एम . एस. भाटिया; सचिव,ग्रामीण विकास विभाग,झारखंड सरकार,श्री अविनाश कुमार ;सचिव वित्त-सह-योजना,झारखंड सरकार,श्री सतेन्द्र सिंह;सचिव, कृषि, झारखंड सरकार, श्रीमती पूजा सिंघल ;क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक, श्री पैट्रिक बारला ;मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री एस॰ मंडल एवं महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, श्री अमूल्य कुमार साहू का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया।

बैठक में उपरोक्त सम्मानित अतिथियों के अलावे श्री एस. आर. जेना,महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक; श्री जी°आर° पाडलकर, महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया; झारखण्ड सरकार के अन्य विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी;झारखण्ड राज्य स्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख; झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक एवं विभिन्न बैंकों,UIDAI व बीमा कंपनियों के उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे ।

स्वागत कार्यक्रम के पश्चात **सचिव, कृषि, श्रीमती पूजा सिंघल** ने अपने वक्तव्य में राज्य में KCC के Rupay कार्ड में conversion पर संतोष जताया परंतू CBI एवं CANARA बैंक में conversion के कम होने के कारण वहाँ के Controlling Heads से विशेष ध्यान देने की बात की | उन्होने उन सभी बैंकों से जहां KCC का Rupay Card मे conversion 60-70% से कम है, वहाँ विशेष ध्यान देने को कहा | हाल ही मे राज्य मे हुए कतिपय घटनाओं का उदाहरण देते हुए उन्होने बैंकों को कृषि ऋण का बकाया अन्य खातों मे उपलब्ध राशि से जबरन चुकता नहीं करने की अपील की | उन्होंने कहा कि राज्य में बैंको द्वारा किसानों से जबरन ऋण वसूली नहीं किया जाना चाहिए। उन्होने किसानों के आय को दोगुने करने से संबन्धित मुद्दे पर बोलते हुये कहा की राज्य में कृषि विकास के लिए पाँच उप क्षेत्र में चिन्हित किए गए है। वो पाँच क्षेत्र है, बीज उत्पादन,दुग्ध उत्पादन ,ई-NAM,मॉडल मार्केटिंग एवं पैक्स तथा लैंप्स का सशक्तिकरण। उन्होने 15 नवंबर 2017 को जमशेदपुर एवं गिरिडीह में दो dairy स्कीम की आधारशिला रखे जाने की जानकारी दी। झारखंड इस वर्ष PMFBY COVERAGE में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा परंतु राज्य में PMFBY के अंतर्गत loanee farmers की कम संख्या (1.13 लाख) पर उन्होने चिंता जाहिर की |कुछ बैंको द्वारा कृषि ऋण वितरण मे ध्यान नहीं देने की बात भी उन्होने प्रमुखता से सभा के समक्ष रखी । उसमे सुधार करने का निर्देश दिया। उन्होंने बैंको से कृषि कार्य के लिए दिये जाने वाले ऋण का कृषि कार्य में ही उपयोग हो, ऐसा सुनिश्चित करने को कहा |

इसके पश्चात **मुख्य महाप्रबंधक ,नाबार्ड ,श्री एस. के . मंडल** ने कृषि संबन्धित मुद्दों पर अपना विचार रखा । उन्होने इस बात पर अपनी चिंता जाहीर की, कि राज्य में CD Ratio का प्रतिशत RIDF के बिना केवल 42% के आस-पास है जिसे अविलंब बढ़ाए जाने कि आवश्यकता है | उन्होने 30% से कम CD Ratio वाले बैंको के लिए MONITORABLE ACTION PLAN बनाने की जरूरत बताया। इसके साथ ही उन्होने नाबार्ड द्वारा SHGs के रेकॉर्ड को digital platform पर लाये जाने की जानकारी दी और JLG एवं FPO के माध्यम से कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण में वृद्धि किए जाने की संभावना पर भी अपने विचार व्यक्त किए |

तत्पश्चात **क्षेत्रीय निदेशक ,आरबीआई ,श्री पैट्रिक बारला** ने अपने संबोधन में गरीब कल्याण मेला,मुद्रा प्रोत्साहन मेला तथा DIGITAL TRANSACTION में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य के सभी बैंको को धन्यवाद दिया। CD ratio में हुए बढ़ोत्तरी के लिए भी उन्होने बैंकों की सराहना की। कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन पर उन्होने गहरी चिंता व्यक्त की और

interest subvention के schemes के फ़ायदों को कृषि ऋणियों को बताने की सलाह दी ताकि इसमे अपेक्षित वृद्धि हो सके | RSETI Trainees के क्रेडिट लिंकेज पर उन्होने बैंको से viable cases को जल्द स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होने municipal area के बाहर भवन निर्माण की मंजूरी दिये जाने के लिए सक्षम अधिकारी की नियुक्ति जल्द किए जाने की बात कही | RBI के नए दिशा-निर्देशों के बावजूद अभी तक 137 चिन्हित गावों मे से 6 मे अभी तक banking outlet की सुविधा नहीं उपलब्ध कराये जाने पर उन्होने अपनी चिंता जाहीर की | ATM में 100 रुपए के नोट के अनुपलब्धता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा की एटीएम में 100 रुपए का नोट उपलब्धता सुनिश्चित की जाए । सिक्कों के लेन-देन से संबन्धित समस्या पर उन्होने कहा की कोई भी बैंक legal tender को लेने से मना नहीं कर सकता है। उन्होने एक महत्वपूर्ण बात एसएलबीसी डाटा reporting से संबन्धित की ,जिसमे उन्होने बताया की एसएलबीसी के डाटा विभिन्न Policy बनाने में उपयोग किए जाते है अतः सभी बैंक को पूरी सावधानी के साथ विश्वसनीय व त्रुटिहीन डाटा एसएलबीसी को प्रेषित किया जाना चाहिए |

इसके पश्चात **सचिव, ग्रामीण विकास श्री अविनाश कुमार** ने अपने सम्बोधन मे कहा कि वो पुराने मुद्दे ही उठा रहे है क्यूंकि एक दो मुद्दों को छोड़ बाकी में और सुधार की आवश्यकता है। बैंकों के पास पड़े SHGs के लंबित आवेदनो का शीघ्र निपटारा किया जाये| **SBI** एवं **BOI** के शाखाओं द्वारा **SHG** आवेदनों को स्वीकार न करना चिंताजनक विषय है। और इसमे संजीदगी दिखने की आवश्यकता है। **CBI** एवं **CANARA BANK** के **SHG CREDIT LINKAGE** के प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। छोटे छोटे कारणों से **RSETI** भवन निर्माण में देरी भी चिंताजनक है। रामगढ़ में जमीन की समस्या का निदान जल्द करने की बात कही तथा एसबीआई के लातेहार में भवन निर्माण में तेजी लाने को कहा। **MNREGA** में **BANK** के कार्य की सराहना करते हुए उन्होने कहा कि अगर कुछ कम उपलब्धि वाले जिलों जैसे कोडरमा, चतरा, दुमका, पाकुड़ एवं गिरिडीह में थोड़ा प्रयास किया जाए तो राज्य में आधार सीडिंग में 95% की स्थिति तक पहुंचा सकता है। उन्होने कहा कि ज़ीरो बैलेन्स वाले खाते एवं जनधन खातों को सामान्य खातों में परिवर्तित किए जाने मे अभी भी परेशानी आ रही है उन परेशानियों को दूर कर लिया जाना चाहिए। **FTO** के द्वारा पेमेंट को तुरंत करने पर भी जोर दिया।लाभूकों के भुगतान के लिए पर्याप्त नगद की व्यवस्था होनी चाहिए । उन्होंने **MNREGA** एवं PMAY के लाभुकों को सरकार द्वारा दिये जा रहे राशि में से ऋण कटौती किये जाने का मामला भी उठाया और ऐसे कृत्यों को ना करने का आग्रह किया।

इसके पश्चात **प्रधान सचिव, समाज कल्याण ,श्री एम. एस . भाटिया** ने अपने सम्बोधन मे कहा कि कई बार physical advice देने के बाद भी लाभूकों के खाते मे अंतरण होने मे महीने लग जाने पर चिंता प्रकट किया।कई CSP द्वारा पूरा भुगतान नहीं करने कि समस्या पर बैंको को CSP/BC को स्पष्ट निर्देश देने के लिए कहा।उन्होने एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड में हो रही आधार सीडिंग के मुद्दे पर जागरूकता फैलाने को कहा।

श्री मदनेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने सम्बोधन की शुरुआत करते हुये कहा कि PMJDY मे confusion नहीं होना चाहिए । PMJDY खाते दोनों तरह के होते है । एक BSBD खाते एवं दूसरा NORMAL SAVING ACCOUNT । BSBD एकाउंट में लेन –देन की कुछ सीमाएं है परंतु PMJDY NORMAL SAVING ACCOUNT में बंदिशे नहीं है।साथ ही उन्होंने बताया कि BC को उनका कमीशन समय पर दे और उनके साथ बैठके भी करें। उन्होने एयरटेल पेमेंटबैंक लिमिटेड में हो रहे आधार सीडिंग के मुद्दे को केंद्रीय स्तर पर उठाने का आश्वाशन दिया। उन्होने मुद्रा प्रोत्साहन अभियान में झारखंड राज्य के सारे बैंक के समुचित भागीदारी के लिए बधाई दी। कृषि ऋण संवितरण में समुचित वृद्धि न हो पाने पर उन्होने चिंता व्यक्त किया। KCC Rupay Card के शत प्रतिशत लक्ष्य पाने के प्रयास के लिए बैंको को कदम उठाने को कहा ।उन्होने कहा कि Dormant खातों को चिन्हित कर आधार सीडिंग करे तो लक्ष्य के करीब तेजी से पहुंचा जा सकता है। उन्होने यह भी कहा कि विभिन्न राज्य में अलग अलग बीमा योजनाएँ चल रही है अभी उनको एक ही योजना के तहत लाने की कार्यवाही चल रही है। राज्य सरकार से भी उन्होने अनुरोध किया की विभिन्न योजनाओ के लाभूकों का बीमा कवर किया जाए। आंध्र प्रदेश का उदाहरण देते हुये उन्होने बताया की आंध्र प्रदेश मे 3 करोड़ लोगो को एक साथ बीमा कवरेज दिया गया। अटल पेंशन योजना मे राज्य मे अच्छी स्थिति न होने पर उन्होने चिंता जाहीर की। उन्होने बताया की राज्य मे विशेष अभियान के लिए वो PFRDA से बात करेंगे। उन्होने SLBC व बैंको से अनुरोध किया की इन योजनाओ के बैनर शाखाओं में लगाने का कार्य अतिशीघ्र करें। शिक्षा ऋण पर विशेष बल देते हुये उन्होने कहा की झारखंड शिक्षा के क्षेत्र मे एक हब की तरह है और राज्य में शिक्षा ऋण में बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होने बताया की शिक्षा ऋण इनवेस्टमेंट की तरह है । किसानो के आय को दोगुना करने के मुद्दे पर उन्होने कहा की राज्य मे खाद्य प्रसंस्करण की अपार संभावनाएं है, अगर उचित ध्यान दिया जाए तो राज्य कृषकों के आय में बढ़ोत्तरी करने मे सफलता पाएगा। उन्होने राज्य मे किसानो के विकास के लिए केंद्र सरकार व बैंकों की अच्छी भागीदारी से अमूल जैसे अभियान की आवश्यकता पर बल दिया।

अपर मुख्य सचिव-सह-विकास आयुक्त श्री अमित खरे ने अपने सम्बोधन मे सीडी अनुपात में वृद्धि के लिए बैंको के कार्य की सराहना की । उन्होने बैंको द्वारा प्रधानमंत्री मंत्री मुद्रा योजना व एसएचजी क्रेडिट लिंकेज में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होने आगामी 15.11.2017 को रांची मे महामहिम राष्ट्रपति जी के राज्य स्थापना दिवस पर झारखंड आगमन पर बैंकों को 1000 करोड़ ऋण संवितरण के लक्ष्य को प्राप्त करने को कहा। तत्पश्चात उन्होने तीन मुख्य बिन्दुओं पर ध्यान देते हुये कहा कि किसानों के आय को दोगुना करने का प्रयास होना चाहिए। इसके लिए कृषि विभाग ,नाबार्ड ,एसएलबीसी व

कृषि विश्वविद्यालाओं की भागीदारी होनी चाहिए। उन्होने माननीय प्रधानमंत्री के SWEET REVOLUTION के तहत राज्य सरकार की भावी योजना पर ध्यान आकृष्ट कराया कि राज्य में इस योजना के तहत महिलाएं प्रतिमाह 4-5 हजार रुपए कमा सकती है। उन्होने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गठित लघु कुटीर उद्यम बोर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि सखी मंडलों को ज्यादा से ज्यादा ऋण का संवितरण सुनिश्चित किया जाए क्योंकि उनके द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पाद को सीधे राज्य सरकार द्वारा purchase किया जा रहा है जिससे उन उद्यमों कि viability पर कोई संदेह नहीं है |उन्होने यह भी बताया कि इनके उत्पाद के लिए मार्केट का इंतजाम सरकार खुद करेगी। दूसरी चर्चा में उन्होने कहा कि अगर गाँव-गाँव मे बैंकिंग कौरेस्पोंडेंट हो तो निश्चित रूप मे गाँव में भुगतान की समस्या से निजात पाया जा रहा है। बीसी के भुगतान के लिमिट को भी बढ़ाया जाना चाहिए। चूंकि अब FTO के माध्यम से पेमेंट हो रहा है तो BC नेटवर्क को मजबूत करना बहुत जरूरी है । उन्होने बीमा संबन्धित मुद्दे पर बोलते हुये कहा कि जैसा श्री मदनेश मिश्रा जी ने कहा कि एसएलबीसी के मीटिंग में बीमा कंपनी कि भागीदारी हो ,अगले एसएलबीसी मीटिंग में NICL के GM को बुलाने की भी बात कही। तीसरी बात उन्होने उद्योग से संबन्धित कहा। उन्होने कहा कि बड़े शहरो में बड़े व मझले स्तर के उद्योग को बैंक को बढ़ कर ऋण देना चाहिए । उद्योगो को वित्तीय मदद के लिए राज्य सरकार भी कुछ नियमों मे परिवर्तन करने वाली है ,राज्य सरकार उद्योग को incentive दे कर राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने में लगी है ऐसे में बैंक के ऋण सहयोग से उद्योगों के नए बनते परिवेश प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा।

व्यवसाय सत्र (BusinessSession):अध्यक्ष के आदेशानुसार, प्रबंधक, SLBC,श्री अतुल भूषण द्वारा व्यवसाय सत्र की कार्यवाही शुरू करते हुए सर्वप्रथम दिनांक 21.08.2017 को आयोजित 60वी एसएलबीसी बैठक के कार्यवृत की संपुष्टि सभा द्वारा कराई गयी |

तत्पश्चात श्रीअतुल भूषण ने एसएलबीसी की 61वीं बैठक में चर्चा किए जाने वाले बिन्दुओं को क्रमवार प्रस्तुत किया।

राज्य सरकार से संबंधित मामले:

नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना:

SLBC द्वारा राज्य सरकार से पिछली बैठक के दौरान तत्कालीन प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,श्री एन एन सिन्हा द्वारा दिये गए जानकारी पर वर्तमान वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया,जिसपर सरकार द्वारा यह बताया गया कि इस मामले में पंचायत को अधिकार दे दिया गया है जिसकी नियमावली अभी बन रही है |नियमावली पंचायती राज विभाग बना रही है । **(Action: राज्य सरकार)**

भूमि पर Online Charge create करना -

इस मुद्दे पर आरबीआई ,नाबार्ड व चेयरमैन ग्रामीण बैंक ने सुझाव देते हुये कहा की अगर जमीन के वर्तमान मालिको की सूचनाएँ अगर land digitization के पोर्टल पर डाल दिये जाए तो बैंक को ऑनलाइन charge create करने मे सहूलियत होगी। **(Action: राज्य सरकार)**

RSETI से संबन्धित मुद्दे-

राज्य सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलने वाली योजना तेजस्विनी (14-24 साल की युवा लड़कियो को कौशल प्रशिक्षण) में RSETI/BANK की भागीदारी के लिए एक अलग से चर्चा करने की बात की गयी। **(Action: राज्य सरकार)**

जमा, क्रेडिट एवं ऋण-जमा अनुपात

इस संबंध मे यह बतलाया गाय कि राज्य के बैंकों के जमास्तर में वर्ष-वार उत्तरोतर वृद्धि दर्ज की जा रही है परंतु ऋण संवितरण के स्तर में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की रफ्तार कम होने के कारण राज्य मे ऋण-जमा अनुपात मे लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी |परंतु इस बार सीडी अनुपात मे बढ़ोत्तरी हुयी है । ज़िला वार चर्चा करते हुये देखा गया की कुछ जिले जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं वहा विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

पलामू, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम एवं जामतारा (25% CD Ratio से कम उप्लब्धि वाले जिले) के LDMs को एक्शन प्लान बना कर सीडी अनुपात बढ़ाने पर विशेष बल देने को कहा गया। इस क्रम में हुई चर्चा में पलामू LDM की अनुपस्थिति पर SBI के वरीय अधिकारियों से बात की गई | साथ ही जामतारा मे PNB के अत्यंत कम CD Ratio पर भी चर्चा हुई | पश्चिमी सिंहभूम के LDM ने बताया कि उनके जिले में इसी माह में 50 करोड़ रु SHG में ऋण देने का निर्णय लिया गया है | चर्चा के क्रम में Canara बैंक द्वारा लगभग 800 करोड़ रु के कम अग्रिम की रिपोर्टिंग किए जाने कि बात सामने आई | श्री अमित खरे ने ऐसे जिले जहाँ सीडी अनुपात कम है वहाँ के LDMs से एसएलबीसी को जानकारी देने का निर्देश दिया और एसएलबीसी को उन बैंक के नियंत्रक प्रमुखों को पत्र लिखने की बात कही । जिन बैंकों एवं जिले का जमा अनुपात 30% एवं 40% से नीचे चला गया है, उन बैंको को विशेष Monitorable action plan बनाकर योजनाबद्ध तरीके से इसे बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया ।

(Action: सभी बैंक एवं सभी LDMs,SLBC)

कृषि ऋण

कृषि ऋण में आई गिरावट के मद्देनज़र हुए विचार-विमर्श में सभी बैंको द्वारा ज्यादा से ज्यादा मियादी कृषि ऋण के संवितरण पर ध्यान देने को कहा गया | इसी क्रम मे नाबार्ड ने विभिन्न योजनाओ के तहत ऋण प्रवाह बढ़ाने की बात कही । इस वर्ष रिपोर्टिंग मे हुये कुछ गलतियों के कारण ऋण मे कमी आई है। बैंक को पुनः सही व समुचित रिपोर्टिंग करने की सलाह दी गयी । **(Action: सभी बैंक एवं सभी LDMs)**

अल्पसंख्यक एवं महिला ऋण

एसएचजी क्रेडिट लिंकेज व स्टैंड अप इंडिया में महिलाओं को ऋण प्रवाह बढ़ाने से इस क्षेत्र में सुधार होगा। झारखंड ग्रामीण बैंक का आंकड़े SLBC BOOK में त्रुटिपूर्ण है और JGB ने बाद मे पत्र द्वारा उस आंकड़े को 470 करोड़ बताया जिससे की महिला ऋण 10800 करोड़ तक पहुंचा। कुछ बैंक जैसे कि बंधन बैंक व एक्सिस बैंक द्वारा महिला ऋण मे शून्य रिपोर्ट किए जाने के कारण भी महिला ऋण के आंकड़े मे कमी आई है। बैंक को पुनः सही व समुचित रिपोर्टिंग करने की सलाह दी गयी। सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, श्री सतेन्द्र सिंह ने सभा में जानकारी दी कि अभी भी कई बैंकों में SHG के बहुत सारे आवेदन लंबित पड़े हैं | यदि इन आवेदनों को स्वीकृति दी जाए और पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार सभी SHG को कम से कम रु 1.00 लाख का ऋण प्रदान किया जाये तो महिलाओं को दिये जाने वाले ऋण प्रवाह मे गुणात्मक वृद्धि दर्ज की जा सकेगी | उन्होने कुछ बैंकों के द्वारा आवेदनों को ना लिए जाने का मुद्दा भी उठाया | खासकर BOI, SBI, JGB, VGB और Allahabad Bank की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया गया |श्री मदनेश मिश्रा ने अपूर्ण आवेदनों से बचने के लिए बैंकों द्वारा Check लिस्ट बनाकर BLOs को देने की बात काही और साथ ही सुझाव दिया कि बैंकों को सप्ताह में एक दिन आवेदनों को जमा लिए एवं scrutiny किए जाने के लिए तय करना चाहिए ताकि किसी भी संबन्धित पक्ष को अनावश्यक परेशानी न हो |

(Action: JSLPS, सभी बैंक एवं सभी LDMs)

वार्षिक ऋण योजना के आधार पर वर्ष 2016-17 की उपलब्धि की समीक्षा

श्री अतुल भूषण ने बतलाया कि पिछले वर्ष के प्रथम छमाही की तुलना मे इस वर्ष के प्रथम छमाही मे कुल ऋण संवितरण मे वृद्धि हुई है परंतु पूरे राज्य में कुल ऋण का o/s पिछले half year की तुलना मे काफी कम हुआ है । कृषि ऋण में इस छमाही में 2000 करोड़ के संवितरण के बाद भी सकल कृषि ऋण मे वृद्धि न होना चिंता का विषय है। SLBC द्वारा सभा में यह जानकारी दी गयी कि BOB के द्वारा कृषि क्षेत्र में रु 250 करोड़ के संवितरण किए जाने के बावजूद कृषि अग्रिम में रु 100 करोड़ की गिरावट दर्ज की गयी है |

(Action: सभी बैंक एवं सभी LDMs)

KCC का Rupay कार्ड मे conversion

Joint Secretary, DFS, श्री मदनेश कुमार मिश्रा जी ने कहा कि राज्य में 97 % रुपे कार्ड दिये जा चुके है पर उनका उपयोग निर्धारित नहीं हो पा रहा है। उनके उपयोग को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। केसीसी ऋण स्वीकृत करते समय ही किसानों को Rupay Card Kit दिये जाने का सुझाव दिया गया | श्री ब्रिज लाल, अध्यक्ष, ग्रामीण बैंक ने ready kit दिये जाने के मामले पर personalized और non-personalized कार्ड की समस्या की ओर सभा का ध्यान दिलाया | **(Action: सभी बैंक)**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

श्री अतुल भूषण ने इस संबंध मे कहा कि एसएलबीसी द्वारा PMFBY से संबन्धित सभी सूचनाओं को साझा करते हुये कहा कि कहीं न कहीं राज्य मे **PMFBY** कवरेज में **loanee** किसानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है ।नाबार्ड ने **PMFBY** कवरेज के तहत फसलों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाने की बात कही।

(Action: सभी बैंक व राज्य सरकार)

सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण (एम एस एम ई)

श्री अतुल भूषण ने इस संबंध मे कहा कि इस वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में MSME sector में बैंको ने अच्छा कार्य किया है और पूरे वित्तीय वर्ष के target के विरुद्ध 50% से ज्यादा की उपलब्धि हो गई है | सभी बैंको से यह आग्रह किया गया कि उन्हे केवल वैसे खातों की रिपोर्टिंग करनी चाहिए जो बैंक के स्वीकृति शर्तों के अधीन CGTMSE coverage के लिए पात्र हैं ताकि वैसे खातों के विरुद्ध CGTMSE coverage की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके |MSE सेक्टर का कुल MSME ऋण में 60 % भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। **(Action: सभी बैंक)**

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

श्री अतुल भूषण ने इस संबंध मे कहा किइस वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में झारखण्ड राज्य में मुद्रा योजना के तहत ऋण के संवितरण में काफी प्रगति हुई है और इस वर्ष लगभग 50 % टार्गेट पूरा किया जा चुका है। पिछले मीटिंग में श्री मदनेश मिश्रा जी के कथन को उद्धृत करते हुये कहा गया कि योग्य कृषि मियादी ऋण **(allied activities)** को मुद्रा योजना के तहत कवर किया जाना चाहिए।

श्री बृजलाल,चेयरमैन,झारखंड ग्रामीण बैंक ने Joint Secretary ,DFS श्री मदनेश कुमार मिश्रा से निवेदन किया कि अगर ग्रामीण बैंक को भी NCGTC कवरेज मिले तो बैंक प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत बहुत अच्छा कर सकती है। **(Action: SLBC एवं सभी बैंक)**

स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना

श्री अतुल भूषण ने स्टैंड अप इंडिया ऋण में उपलब्धि बजट से काफी कम रहने की सूचना दी । दो तिमाहियों मे मात्र 91 ऋण स्वीकृत होना चिंताजनक है। श्री सतेन्द्र सिंह,सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग ने कहा है की स्वीकृत ऋण को संबन्धित पोर्टल मे समय सीमा में अपलोड कर लेना चाहिए।SLBC द्वारा सभा में उपस्थित सभी बैंकों से यह आग्रह किया गया कि SUI योजना के तहत स्वीकृत किये गए सभी ऋणों को पोर्टल पर अविलम्ब upload किया जाये ताकि इस sector में हुई वास्तविक प्रगति का पता चल सके |

(Action: सभी बैंक एवं सभी LDMs)

शिक्षा ऋण

शिक्षा ऋण पर हो रहे चर्चा पर बात करते हुये ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अविनाश कुमार द्वारा यह बात सामने लाई गयी की ऋण से जुड़े processing charges को पहले ही आवेदकों को बताना चाहिए। ऋण स्वीकृति/अस्वीकृति के पश्चात शुल्क वसूली बिना बताए करना कहीं कहीं पारदर्शिता पर सवाल उठता है। श्री पैट्रिक बारला,क्षेत्रीय निदेशक,आरबीआई ने सभा को बताया की IBA द्वारा इस दिशा मे circular दिया जा चुका है की ऋण से संबन्धित charges पूर्व में ही आवेदकों को बताना है।Joint Secretary ,DFS श्री मदनेश कुमार मिश्रा ने कहा की उनके पास बहुत सारे शिक्षा ऋण से जुड़े शिकायत आते है जिनमे बैंक के द्वारा ऋण नही स्वीकृत करने के बारे मे बराबर लिखा जाता है।सभी बैंक को चाहिए की शिक्षा ऋण मे ऐसी शिकायत उत्पन्न होने से बचे और शिक्षा ऋण को एक इनवेस्टमेंट के रूप मे ले।**(Action: सभी बैंक)**

एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

इस विषय पर SLBC द्वारा इस वित्तीय वर्ष में हुई कुल उपलब्धि जिनमे नाबार्ड एवं JSLPS द्वारा promoted SHGs भी शामिल हैं, का ब्यौरा सभा को दिया गया | सितंबर माह में बैंकों द्वारा अच्छी संख्या में **SHG financing** किए जाने पर सभी बैंकों को बधाई दी गयी और सभी **Pending Applications** को जल्द से जल्द निस्पादित किए जाने के लिए कहा गया । **(Action: सभी बैंक एवं सभी LDMs)**

प्रधानमंत्री जन धन योजना

PMJDY खाते में Rupay Card activation को बढ़ाने की जरूरत है। सिर्फ 50% ही रुपे कार्ड का एक्टिव होना चिंताजनक है । श्री सतेन्द्र सिंह,सचिव, योजना-सह-वित्त विभागने PMJDY खातों मे चार्ज काटे जाने पर भी दुख प्रकट किया। उन्होने कहा कि छात्रवृति के पैसो से 100 रुपए काट लिए जाते है। उन्होने सरायकेला जिला का उदाहरण देते हुये कहा कि बैंक द्वारा यह बताया जाता है की बैंक मे सिस्टम ने पैसा काट लिया,यह जवाब चिंताजनक है। बिना आदेश के सिस्टम पैसा कैसे काट सकता है ? इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होने यह भी कहा की जब सरकार की सभी योजनाएँ DBT द्वरा संचालित है तो ऐसे मे ये घटना राज्य का, गलत चित्रण केंद्रीय स्तर पर करेगा। अतः ऐसी गलतियों को तुरंत सुधार लेना चाहिए।श्री पैट्रिक बारला ,क्षेत्रीय निदेशक,आरबीआई ने कहा कि PMJDY NORMAL KYC खाते में ZERO बैलेन्स पर कोई भी चार्ज नहीं लेना चाहिए। श्री सतेन्द्र सिंह,सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग ने कहा कि राज्य के नगड़ी प्रखण्ड को **PDS** के **DBT** के लिए पायलट प्रोजेक्ट ले लिए चुना गया है। सभी नियंत्रक प्रमुख जिनके बैंक की शाखाएँ नगड़ी प्रखण्ड मे है,उन्हे शत-प्रतिशत आधार मैपिंग तथा ज़ीरो बैलेन्स खातों को खोलने का कार्य जल्द पूरा कर लेना चाहिए।उन्होने **BC** तंत्र को मजबूत करने की बात कही। उन्होने उदाहरण देते हुये कहा कि अगर किसी कारणवश डीबीटी के पश्चात बैंक से पैसा नहीं मिल पाया और लाभूक राशन नहीं खरीद पाये ,और कही किसी तरह की दुर्घटना हो गयी तो परेशानी हो सकती है। अतः सभी को इस पायलट प्रोजेक्ट को हर तरह

से सफल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।**(Action: SLBC, co-opertaive बैंक, अन्यसभी बैंक एवं सभी LDMs)**

बैंक शाखाओं का खोला जाना

श्री अतुल भूषण ने सभा को जानकारी देते हुए कहा कि आरबीआई के बैंकिंग आउटलेट के संबंध मे नए दिशानिर्देश बैविवि. बीसी.बीएपीडी.सं.69/22.01.001/2016-17 दिनांक 18 मई 2017 के अनुसार झारखण्ड में चिन्हित किये गए 137 गाँवों में128 गाँव मे बैंक की शाखा या FIXED LOCATION BC खुल चुके हैं। बाकी बचे 6 गाँवों में शाखा का खोला जाना अथवा BC की नियुक्ति लंबित हैं, जिनमे Central Bank of India के 2 centres, United Bank of India के 1 centre, Axis Bank, Canara Bank एवं Vijaya Bank का 1-1 centre शामिल है | CBI ने दोनों गांवों मे उनके लिए feasilibility न होने कि बात कही।उन्होने दोनों केंद्र को नजदीक के बैंक से कवरेज कराने को कहा । वही एक्सिस बैंक,यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया व विजया बैंक ने एक महीने के अंदर केंद्र को कवर कर लेने कि बात कही।केनरा बैंक ने 18 नवंबर को अपने केंद्र में शाखा खोलने कि बात कही। **(Action: CBI, UBI, Canara Bank, Axis Bank एवं Vijaya Bank)**

NON PERFORMING ASSETS (एनपीए)

राज्य में भारी संख्या मे सर्टिफिकेट केसेज का निष्पादन के लिए पेंडिंग होना एक चिंता का विषय है।श्री अंकेश जैन ,उपमहाप्रबंधक ,यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सभा को SARFAESI एक्ट के तहत possession के लिए DC/DM ORDER के लिए आवेदनों का लंबित होना चिंताजनक है। अगर इस दिशा मे कुछ ठोस कदम लिए जाए तो बड़े defaulters से recovery की जा सकेगी । श्री अमित खरे ने कहा कि हर जिले के सबसे big defaulters की सूची बैंक SLBC को उपलब्ध कराये । उस सूची को सम्बद्ध DC को कारवाई हेतु प्रेषित किया जाए। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में एक video conferencing कर के कारवाई की समीक्षा की जाए। RBI के क्षेत्रीय निदेशक ने NPA sector का विस्तृत विश्लेषण करने की सलाह दी | **(Actio : SLBC/सभी BANKS)**

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

Municipal Administration के निदेशक श्री आशीष सिंघमार ने सभा को बताया कि CLSS के अंतर्गत PMAY स्कीम एवं NULM के अंतर्गत बैंको द्वारा काफी कम ऋण दिया गया है और इसमें अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है |उन्होंने interest subsidy claim में बैंको द्वारा देरी किये जाने और इन schemes के अंतर्गत बैंको में पड़े लंबित आवेदनों की तरफ सभा का ध्यान आकृष्ट कराया |इसके साथ ही उन्होंने मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत किये गए ऋण खातों के NULM scheme में conversion की बात भी

बताई|उन्होने यह भी कहा कि PMAY से संबन्धित रिपोर्ट SLBC अपने स्तर पर भी ले । उन्होने अपने स्तर पर एक फ़ारमैट बनवा कर उसे SLBC को देने की बात कही और PMAY को एक अलग agenda के रूप में चर्चा करने की बात कही।उन्होने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत ऋण को NULM के तहत परिवर्तित करने से 2 % अतिरिक्त ब्याज मे छुट मिलने की बात भी बताई एवं बैंक से इस दिशा मे कार्य करने का आग्रह किया।

(Action: HUDCO, NHB, राज्य सरकार, सभी बैंक एवं सभी LDMs)

RSETI एवं FLCC

PNB द्वारा रामगढ़ जिला में भवन निर्माण जमीन की समस्या के कारण लंबित है। बैंको से आग्रह किया गया कि ज्यादा से ज्यादा RSETI द्वारा trained अभ्यर्थियों को लोन दिये जाएँ|

(Action: सभी बैंक, PNB एवं राज्य सरकार)

विविधकार्यसूची

बैंक के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध कारवाये जाने के लिए SLBC की तरफ से राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

सभा के अंत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री जी. आर. पाडलकर ने सभी गणमान्य अतिथियों, प्रतिभागियों एवं मीडिया का धन्यवाद ज्ञापन किया । तत्पश्चात एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री प्रसाद जोशी ने सभी का धन्यवाद करते हुए सभा समाप्ति की घोषणा की ।

दिनांक : 27.11.2017.

(प्रसाद जोशी)
महाप्रबंधक, एस. एल. बी. सी